

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं B.S.T 59 बस्ती, वर्ष 46 अंक 83 बुधवार 16 अक्टूबर 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या-फैजाबाद के एक साथ प्रकाशित पृष्ठ 4मूल्य:3.00 रूपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

देवी प्रतिमाओं का विस्मर्जन 17 को

भारतीय बस्ती संगठनद्वारा- 17 अक्टूबर को होना। अग्र प्रतियोगिताओं और अग्र पुलिस अधीक्षक द्वारा दुर्गा प्रतिमाओं का विस्मर्जन सख्त अज्ञान करने हेतु विस्मर्जन सख्त अज्ञान का अग्रण कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा विभागियों की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया तथा आवश्यक को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मौके पर संबन्धित अधिकारी, कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मारपीट में महिलायें घायल

भारतीय बस्ती संगठनद्वारा- बनकटी (बस्ती)। लालगंज थाना क्षेत्र के भिदहा गांव में सोमवार शाम को दो पक्षों में मारपीट हो गया जिसमें दोनों पक्षों की महिलाएँ चोटिल हो गईं। मिली जानकारी के अनुसार बस्ती महिला मार्ग पर गौरा उषाक याय गण के पास एक दुकान पर अग्रसर पुत्र हारिकान एवं राजकुमार पुत्र शिवनाथ निवासी ग्राम भिदहा थाना लालगंज में कुछ कहां - सुनी हुआ फिर दोनों अपने घर गए झगड़ की जानकारी दी, तभी दोनों परिवार सकुने में आ गए और दोनों बच्चों में हाथापाई या हाकी उड़ते चलने लगे इस समय धरती की महिलाएँ बड़ लड़कियों की बीच बचाव के लिए आ गए जिसमें एक पक्ष की रेखा पुत्री शिवनाथ 24 वर्ष को सिर में चोट लग गई तथा दूसरे पक्ष में चंचल पुत्री हारिकान को भी चोट आई परिजनो द्वारा रेखा पुत्री शिवनाथ को अग्रमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है।

मंदिर से दान पात्र चुराने का प्रयास

भारतीय बस्ती संगठनद्वारा- बनकटी (बस्ती)। लालगंज थाना क्षेत्र के देईसांड स्थित देई माता मंदिर पर सोमवार देर रात अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर में रखा दान पत्र का ताला तोड़ चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था, तभी मंदिर से कुछ ही दूरी पर जिला प्रमाण सुन कर वापस घर लौटे रहे जाणकारी द्वारा कुछ सुरवागणों या आवाज सुनकर प्रामोण मंदिर पर पहुंचे तो प्रामोणों के आने का अज्ञान पाकर चोर भागने में सफल हुए। लेकिन चोर कुछ ले जाने में असफल रहे (तारा मामला मंदिर में अज्ञान सी ली टी भी कमरा में केव है। प्रामोणों द्वारा धान पर तहरीर कर देखा गया कि इस तरह चोरी का प्रयास कई बार हो चुका है और कोई आस - पास का ही व्यक्ति प्रतीत होता है। थाना प्रभारी लालगंज सुनील कुमार गौड़ ने बताया कि मामला सज्जान में आया है, जानकारी की जा रही है।

फसलों का अवशेष न जलायें किसान

भारतीय बस्ती संगठनद्वारा- बनकटी। फसलों के अवशेष जलाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए पारली प्रबंधन आवश्यक है। उन्नत जानकारी देते हुए संयुक्त कृषि निदेशक अविनाश बन्द तिवारी द्वारा मण्डल के जनपदों में कृषकों को जागरूक करते हुए फसल अवशेष न जलायें जाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि पारली जलाने से मृदा में उपलब्ध लाखों बैक्टीरिया जल जल रहे तथा होने के चलते से रूद्धनर अवशेष होने के साथ मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है तथा पैदावार में गिरावट आती है। उन्होंने कहा कि कृषक भाई फसल अवशेष मृदा में ही मिलाकर भूमि में जोड़ना ही एवं उर्वरा शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं।

महाराष्ट्र, झारखण्ड के साथ 49 सीटों पर उपचुनाव घोषित

नई दिल्ली (आभा)। महाराष्ट्र और झारखण्ड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। झारखण्ड में जलवा राउड 13 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 तारीख को होगा। उसी दिन महाराष्ट्र में भी वोटिंग होगी। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे एक साथ ही 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। झारखण्ड के कई जिले निर्वाचन प्रमांति हैं और सुरक्षा की वित्ताए रहती हैं। इसी के चलते दो राउंड में मतदान करने का फैसला लिया गया है। फिर भी यह बड़ा फैसला है क्योंकि 2019 में यहाँ 5 चरणों में मतदान कराया गया था। इन दोनों राज्यों के साथ ही 13 नवंबर को मतदान करा लिया जाएगा और एक साथ ही 23 नवंबर को मतदान करा लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 13 नवंबर को मतदान करा जाएगा। उत्तराखण्ड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर को कराने का फैसला किया गया है।

विधायक योगेश वर्मा के पिटाई मामले में कुर्मी महासभा ने सौपा ज्ञापन

योगेश वर्मा को अथियका संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह और उनके साथियों द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जिस तरह से मारा पीटा, गाड़ियाँ दीं, यह शिथिलियाँ वित्ताजनक है। दोगियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई न की गई तो भारतीय कुर्मी महासभा आन्दोलन को मजबूर रूप में। ज्ञापन सांने वालों में मजबूर शरण से बंदी प्रसाद चौधरी, अशोक कुमार वर्मा, घनशराम चौधरी, विद्याराम चौधरी, मायाशराम चौधरी, अशोक कुमार चौधरी, अरविन्द पटेल आदि शामिल रहे।

भारतीय बस्ती संगठनद्वारा- बस्ती। लखीमपुर खीरी के सदर विधायक योगेश वर्मा की कुर्मी गौरा मारने पीटने का मामला तूल कण्डला जा रहा है। मंगलवार को भारतीय कुर्मी महासभा प्रश्न प्रश्न के आवाहन पर जिलाखण्ड का निवेदन कुर्मी वर्मा प्रश्न सचिव आर.के. सिंह पटेल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मामा किया गया कि दोगियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

ज्ञापन सांने के बाद डा. विजय कुमार वर्मा ने कहा कि लखीमपुर खीरी के सदर विधायक

विधायक योगेश वर्मा के साथ दुर्व्यहार के विरोध में मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

ज्ञापन देने के बाद अखिल भारतीय कुर्मी बस्ती महासभा के जिलाध्यक्ष अशोक वर्मा के नेतृत्व में विधायक योगेश वर्मा और उनके साथियों द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दुर्व्यहार किये जाने के मामले में दोगियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

ज्ञापन देने के बाद अखिल भारतीय कुर्मी बस्ती महासभा के जिलाध्यक्ष अशोक वर्मा के नेतृत्व में विधायक योगेश वर्मा और उनके साथियों द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दुर्व्यहार किये जाने के मामले में दोगियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

दलितों पर बढ़ते अत्याचार, उगाही, उष्पीड़न के विरोध में राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

भारतीय बस्ती संगठनद्वारा- बस्ती। भारतीय दलित वर्ग संसा के राष्ट्रीय सचिव साधू शरण आर्य ने मंगलवार को संघ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। मांग किया कि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे दलित उष्पीड़न के मामलों की उच्च स्तरीय जांच करवाकर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के साथ ही दलितों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की करायें जाए। राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में भारतीय दलित वर्ग संघ के राष्ट्रीय सचिव साधू शरण आर्य ने कहा है कि पूर्वजन्म के साथ ही उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में दलितों के उष्पीड़न मामलों में प्रभावी कार्रवाई न होने से दलितों का मनोबल कम हो रहा है। अतः दलितों के साथ दलित उगाही, ऊष्पीड़न में जेल भेज दिने जायें, दलितों के मजदूर लगातार बढ़ रहे हैं। देश में नरसंहार का सबसे बड़ा शिकार अनुप्राणित जाति-जनजाति के लोग हैं मंदभाव को दूर करने के लिए

डीएम ने किया औचक निरीक्षण

लोकमार्ग में भी नांदेड सीट पर लेकमार्ग उपचुनाव होना है। इसकी लिए भी 20 नवंबर को एक साथ ही मतदान कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह 10 की बजाय कुल 9 विधानसभा सीटों पर ही उपचुनाव होगा। यूपी में अयोध्या की मिलकौपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान करा लिया जाएगा और एक साथ ही 23 नवंबर को मतदान करा लिया जाएगा। उत्तराखण्ड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर को कराने का फैसला किया गया है।

डीएम ने किया औचक निरीक्षण

भारतीय बस्ती संगठनद्वारा- बस्ती। जिलाधिकारी रवीश वर्मा ने विकास खण्ड बहादुरपुर के अज्ञान विभाग प्रेरण पृष्ठ उद्योग प्रशासन प्रोडक्शन ग्राम खंडेआपट, खाद्यान्न महल शाप ग्राम कुर्मी, कौली इण्टरलाइन रोड, सखिबिन उच्च प्राथमिक विद्यालय कुर्मी, ग्राम अरसडा से पिपरा गौमन रोड तथा नालिका कस्तूरवा गौली आवासीय बिल्डिंग विद्यालय नगर थापार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सखिबिन अतिकारीयों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया और शिक्षकगण उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि निर्माणधीन कार्यों में मानक के अनुसार गुणवत्ता का विधि ध्यान रहे। सखिबिन उच्च प्राथमिक विद्यालय कुर्मी पर निरीक्षण के दौरान सखिबिन अतिकारीयों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया और शिक्षकगण उपस्थित रहे।

जांच की जगह डीपीआरओ पर मामले में लीपापोती का आरोप

भारतीय बस्ती संगठनद्वारा- बस्ती। अतिकारीयों की मनमानगी के चलते आम जनता से लेकर के खास लोगों को भी छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ता है वहीं कारण है कि आम जनता का प्रशासन के रवैये पर संवात खड़ा होने लगता है। ताजा मामला बस्ती जनपद के सदरदोहा विकासखण्ड के अमरीची युवाली ग्राम पंचायत का है जहां पर ग्राम पंचायत के विकासकर्ता चौधरी रवीश वर्मा ने जिलाधिकारी वस्ती रवीश वर्मा को शिकायत प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि ग्राम पंचायत अमरीची युवाली में प्रशासन और सचिव के विरुद्ध संसा के साथ वित्त एवं कौली विभाग के पैसे को प्रशासन और प्रशासन के खाते में मुतातान कर उगाह करवाकर कर लिया गया है वहीं ग्राम पंचायत में एक युवाली माली के मरम्मत के नाम पर पैसे का गोमाला किया गया है। शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र को

घटनाओं को गंभीरता से लेकर न्याय दिलायें सरकार-साधू शरण आर्य

सरकार के प्रयास सकारि साहित हो रहे हैं। अतः पर दलितों की सुरक्षा में के बचाव है जिससे दलितों का मनोबल बढ़ गया है। बस्ती, नरसंहार का सबसे बड़ा शिकार अनुप्राणित जाति-जनजाति के लोग हैं मंदभाव को दूर करने के लिए

यूपी में 9 सीटों पर 13 नवम्बर को होंगे मतदान

लखनऊ (आभा)। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों का संसदीयकाल करे जा रहे उपचुनावों का संकेत तैयार हो गया है। सभी सीटों पर एक साथ 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतदान के साथ नतीजे घोषित हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को यूपी की दस विधानसभा सीटों में से नौ सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। अयोध्या की मिलकौपुर सीट पर विलहाल सीट है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी वोटिंग होने उन्में मैनुपुरी की करल, अलीगढ़ की करल, बिजनौर की मौजूपुर, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद की गाजियाबाद, मिर्जापुर की मन्ना,

जयन्ती पर याद किये गये पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम

भारतीय बस्ती संगठनद्वारा- बस्ती। अपना दल एस द्वारा मंगलवार को अल्पसंख्यक मंच जिलाखण्ड विभाग अहमद के संयोजन में कटरा चौरागे के निकट पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयन्ती पर याद किया गया। अपना दल एस के प्रदेश सचिव अग्रिमयु पटेल ने कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुये कहा कि डा. कलाम का साधना पूर्ण जीवन नए-नए संस्कारों को धारण कर उभरे सिद्ध करने के लिए साहस व ऊर्जा देता है। विरासत भेना डॉ कलाम का जीवन देश के युवाओं को गर्व स्रोत व संपर्ण के साथ राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने पूर्व युविया के सामने ज्ञापन, सादर की संघर्ष की उल्लेख मिलात और सांने के हैं। जिलाखण्ड राजमणि पटेल ने कहा कि अब्दुल कलाम का भारत और उसके अनेक की युवा पीढ़ी को लेकर उन्का प्यार और विश्वास कितनी से गिपा नहीं है। हर साल 15 अक्टूबर को देश और दुनिया भर में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में विद्य छात्र दिवस भी मनाया जाता है। उनके जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम संयोजक निरेश अहमद ने कहा कि लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में जाने जाने वाले डॉ. कलाम ने अपना अतिकार्य जीवन

डा. कलाम से प्रेरणा लें युवा-अग्रिमयु पटेल

युवा छात्रों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित कर युवाजीवन पटेल, प्रदीप रसत 'राना' पटेल, प्रदीप पण्डेय, इन्दुवती, रामनाथ शिविर का उद्घाटन किया।

मेले में बिछड़ों को मिलाने के लिये खोया पाया शिविर का उद्घाटन

भारतीय बस्ती संगठनद्वारा- बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुश वर्मा ने कम्पनीबाग के निवृत्त समाज पर विवरण जन कल्याण सेवा समिति द्वारा उप्य प्रवेश गोस्वामी के संयोजन में संवाहित बिछड़ों मिले, खोया पाया माध्यम शिविर का उद्घाटन किया।

डा. कलाम युवाओं के लिये प्रेरणा है। यह आस सृजन की तरह समकाला संसाधन के अनुसार 18 अक्टूबर को अग्रिमयु के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएंगे। 25 अक्टूबर तक नामांकन शुरू है।

समाजवादियों ने जयन्ती पर किया पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान पर विमर्श

भारतीय बस्ती संगठनद्वारा- बस्ती। मंगलवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयन्ती पर याद किया गया। उपस्थित लोगों ने डा. कलाम के विचार पर माल्यार्पण के साथ उनके योगदान पर कर्वा किया। पूर्व विधायक राजनीति पण्डेय ने कहा कि उनकी राजनीति विचार छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह दिन छात्रों को यह बताता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी महत्ता, संपर्ण और सही दिशा में प्रयास करना आवश्यक है। डॉ कलाम शिक्षा के प्रथम सन्देश थे और भारत थे कि छात्रों में दुनिया में बड़ा बदलाव लाने की शक्ति है। वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेषकर निस्वावल विकास और अतिरिक्त अनुसंधान में अपने काम के लिए जाना जाते थे, लेकिन उनमें युवाओं को पढ़ाने और प्रेरित करने का भी विश्व प्रसूत था। उनका योगदान संदेव याद किया जाएगा। पूर्व राज्य मंत्री श्रीपति सिंह, दरशासक मिश्र, रामाराम यादव, मो स्वातेद, जनील अहमद ने कहा कि

उनकी जयन्ती पर याद करने वालों में मुख्य रूप से कम्क युवक, रन बहादुर यादव, अरविन्द सोनकर, सुरेन्द्र सिंह छोटे, निरेश अहमद, दरशासक अहमद, रविन्द यादव, हुदयार यादव, पाण्डेय, गौरीशंकर पाण्डेय, मोला राम गो, दरशासक आदर को समाजवादी दल, एसे उनके विचारों ने देश को पूर्व दिशा दिया। कटिण परिस्थिति में उन्होंने वह करी विद्यालय को अहमय बनाया जाता था। वे संदेव याद किया जाएगा। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को



अग्रिमयु पटेल का कटौरी, संघल की कुदरकी और कानपुर की सीसासक सीट है।



युवा छात्रों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित कर युवाजीवन पटेल, प्रदीप रसत 'राना' पटेल, प्रदीप पण्डेय, इन्दुवती, रामनाथ शिविर का उद्घाटन किया।



डा. कलाम से प्रेरणा लें युवा-अग्रिमयु पटेल



समाजवादियों ने जयन्ती पर किया पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान पर विमर्श



उनकी जयन्ती पर याद करने वालों में मुख्य रूप से कम्क युवक, रन बहादुर यादव, अरविन्द सोनकर, सुरेन्द्र सिंह छोटे, निरेश अहमद, दरशासक अहमद, रविन्द यादव, हुदयार यादव, पाण्डेय, गौरीशंकर पाण्डेय, मोला राम गो, दरशासक आदर को समाजवादी दल, एसे उनके विचारों ने देश को पूर्व दिशा दिया। कटिण परिस्थिति में उन्होंने वह करी विद्यालय को अहमय बनाया जाता था। वे संदेव याद किया जाएगा। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"-वेडेल फिलिपा

भारतीय बस्ती

बस्ती 16 अक्टूबर 2024 बुधवार

सम्पादकीय

धन बला की राजनीति

राजनीति में धनाढ्य लोगों, बाहुबलियों तथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का सक्रिय होना, अब भारतीय जनतांत्रिक व्यवस्था का चरित्र बन चुका है। कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, उनकी उपस्थिति हर राज्य व केंद्र की राजनीति में नजर आती है। हाल ही में संपन्न हरियाणा विधानसभा के चुनावों के बाद आई एक रिपोर्ट ने इस मुद्दे को फिर विमर्श में ला दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में चुने गए 96 फीसदी विधायक करोड़पति हैं। वैसे यह कहना कठिन है कि जनप्रतिनिधि नामांकन भरते समय कितनी ईमानदारी से अपनी सफेद कमाई को दर्शाते हैं। जबकि अश्वेत कमाई का तो कोई जमिर ही नहीं होता। आर्थिक आंकड़ों से खेलने वाली एक पूरी बिरादरी स्याह को श्वेत बनाने के खेल में परागत होती है। फिर करोड़पति की कोई सीमा नहीं कि उसकी संपत्ति कितने करोड़ों में है। रिपोर्ट में दूसरी चौकाने वाली बात यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीतने वाले माननीयों में 13 फीसदी का आपराधिक अतीत मुकादमा है। इनमें से कई पर गंभीर अपराधों के लिये मुकदमें चल रहे हैं। यह मतदाताओं के लिये भी आत्ममंथन का समय है कि प्रत्याशी की हकीकत को जानते हुए भी उसे जिताने लायक वोट कैसे मिल जाते हैं। यूं तो जुबानी तौर पर हर बड़ा राजनीतिक दल लोकतंत्र में राजनीतिक शुचिता की वकालत करता नजर आता है, बड़ी-बड़ों दोहराता है। लेकिन हकीकत में स्थिति वही 'ढाक के तीन पात'। चुनाव आते ही ऐसी नकारात्मकता प्रत्याशी की जीत की गारंटी बन जाती है। जनता भी अब सुन-सुनकर थक चुकी है। उसे भी लगने लग कि शायद यही विसंगति हमारी नियति बन गई है। वैसे राजनेताओं के साथ ही मतदाता भी इस राजनीतिक विद्रूपता के लिये कम जिम्मेदार नहीं हैं, जो छोटे-छोटे प्रलोभनों के लिये मतदान करते वक अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। दरअसल, आजादी के सात दशक बाद भी मतदाता को इतना विवेकशील बनाने की पहल राजनेताओं ने नहीं की कि वह अपने विवेक से राष्ट्रीय हितों को देखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

बहरहाल, करोड़पतियों के जनप्रतिनिधि संस्थाओं में वर्चस्व का एक निरंकुश साफ है कि आम आदमी के लिये चुनाव लड़ना अब दूर की कौड़ी बन गई है। यह कथन अब किताबों तक सीमित रह गया है कि जनतंत्र जनता द्वारा , जनता का और जनता के लिये होता है। कहा जाता है कि आजादी के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में राजस्थान का एक विधायक ऐसा भी था, जिसके पास जयपुर जाकर शय्यप्रग्रहण समारोह में शामिल होने के लिये टिकट के पैसे तक नहीं थे। तब लोगों ने उनकी मदद की। बहरहाल, हमें स्वीकार करना होगा कि भले ही राजनीति में अब धनबल व बाहुबल अपरिहार्य हो, लेकिन इस स्थिति के लिये जनमानस भी कम जिम्मेदार नहीं है। हमें साचेँ कि क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद और छोटे-छोटे प्रलोभनों के लिये हम ऐसे प्रत्याशियों को जनप्रतिनिधि संस्थाओं में क्यों भेज देते हैं, जो वहां जाना लायक ही नहीं होते। हमें यह भी सोचना होगा कि मुफ्त की रेवडिडियों के अलावा चंद रुपयों व सुरा के लिये सुर बदलने वाले लोग कौन हैं? कहीं न कहीं यह हमारे सामाजिक मूल्यों के परामव का प्रमाण भी है। जब कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा होने का गौरव रखते हैं, तो यही बड़प्पन हमारे लोकतांत्रिक व्यवहार में दिखायी देना चाहिए। हमें अपने वैश्वकीय वोट के दायित्व का बोध भी होना चाहिए। उसकी गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे लोकतंत्र पर दागी और धनाढ्य लोगों का वर्चस्व स्थापित न हो। हम ध्यान रखें कि जब करोड़पतियों के हाथ में सत्ता की बागडोर आती है तो उनकी संपत्ति अगले चुनाव तक दिन दूनी-रात चौगुनी गति से बढ़ती है। ऐसे जनप्रतिनिधियों का लक्ष्य अपने लिये ही नहीं बल्कि आने वाली सात पीढ़ियों के लिये धन-संपदा जताना होता है। जिसमें हमारी जरूरतों को पूरी कराने वाली व्यवस्था के लिये आवंटित धन तथा अनैतिक तौर-तरीकों से जुटाया पैसा भी शामिल होता है। जो भ्रष्टाचार की अंतहीन शृंखला को जन्म देता है। दरकते पुलों, धरती सड़कों, बीमार अस्पतालों तथा बहदाहल शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार की परिणति के रूप में देखा जा सकता है।

नये जिलों के सृजन का औचित्य



-अशोक लवासा-

कहने को 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'- एक बहिया और उपयुक्त नारा है। अन्य लोकप्रिय मुखवार यह है कि मास्त की शासकीय संरचना केवल तीन शक्तिशाली स्तरों पर टिकी है - प्रथममंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधीशय जिसको लेकर आमजन पर काज जाता है कि पीएम-सीएम-डीएम नामक त्रिभुज भारत का राजकाज चलाती है।

निभाजन के समय भारत में जिलों की संख्या सदीक रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन 1951 में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना के समय कुल 402 जिले थे। ये जिले 27 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) में फेले हुए थे। न्यूनतम आंकड़े के अनुसार, देश में 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश और 806 जिले हैं। इनमें 6 जिले हाल ही में लदाख में जोड़े गए हैं जो कि सबसे नया केंद्रशासित प्रदेश है। अब इसकी स्थापना 2019 में हुई है। अब इसके जिलों की संख्या 2 से बढ़कर 7 हो गई है।

जिनम के जिलों की संख्या साल 1951 में 402 थी व साल 1991 तक उसमें 74 नए जिले बनेकर जुड़े। अक्टूबर के (1991-2001) में 117 नए जिले जोड़े गए, 2001 से 2011 के बीच इनकी संख्या 47 रही। पिछले 13 वर्षों में 166 नवीन जिलों का निर्माण हुआ है। साल 1951 में,



आंध्र प्रदेश में 19 जिले थे और हैदराबाद सूबे में 17 जिले थे, आज आंध्र प्रदेश में 26 तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बने तेलंगाना में 33 जिले हैं। इसी तरह, हम ही यह संख्या 18 से बढ़कर 35 हो गई, बिहार में 13 से 38, दिल्ली में 1 से 11, हिमाचल प्रदेश में 6 से 12, जम्मू-कश्मीर में 6 से 20, पंजाब में 12 से 23, ओडिशा में 13 से 30, राजस्थान में 21 से 50, उत्तर प्रदेश में 40 से 75 और पश्चिम बंगाल में संख्या 15 से 30 हो गई है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1956 लागू होने के बाद बनाए गए कुछ नए राज्यों का विकास चौकाने वाला है। हरियाणा में 22 जिले हैं, जबकि 1966 में इसके निर्माण के समय 7 जिले थे। तेलंगाना की गिनती 10 से बढ़कर 33 हो गई है, उत्तराखंड में 9 से 13, झारखंड में 12 से 24 और छत्तीसगढ़ में 16 से बढ़कर 33 जिले हो गए। एक नए जिले का निर्माण, जो कि अनियंत्रित रूप से एक प्रशासनिक इकाई होता है, लदाख नहीं यह करते वक किसी भी तर्कसंगत सिद्धांत का

पालन किया जाता है। जिला बनाने के लिए कोई परिभाषित भौगोलिक या सांख्यिकीय मानदंड नहीं है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जिसका क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किमी और जनसंख्या 20,92,371 है। सबसे छोटा जिला पम्हे है, जिसका क्षेत्रफल 8.69 वर्ग किमी, और जनसंख्या 41,816 है। आवादी के हिसाब से उत्तर 24 परगना सबसे बड़ा जिला है और 1,00,09,781 लोग वसते हैं और कुल क्षेत्रफल 4,094 वर्ग किमी है, जबकि सबसे कम आवादी दिगवां जिले की है जहां पर 8,004 निवासी हैं और 9,129 वर्ग किमी क्षेत्र है। अधिभाजित लेह जिले की जनसंख्या 1,33,487 और क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किमी था यद्यपि कारगिल की जनसंख्या 1,40,802 और क्षेत्रफल 14,086 वर्ग किमी था। अब कारगिल से काठकर ड्रास और झॉंस्कार को जिला बनाया गया है और लेह को विभाजित कर चांगथांग, नुबा और शाम घाटी नामक जिले बनाए गए हैं।

यह सब है कि मूल लदाख जिला प्रशासन चलाने के लिलाज से अत्यंत विशाल था। कारगिल और लेह संस्कृति रूप से अलग-अलग थे। इस कारण 1979 में कारगिल को एक अलग जिले के रूप में रखा गया। छोटा किए जाने के बावजूद लेह जिला भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा जिला बना रहा। भारत में नए जिले का निर्माण आम तौर पर किसी वस्तुनिष्ठ मानदंड के बिना राजनीतिक मांगों का परिणाम होते हैं। मसलत, लदाख के मामले में, कारगिल से अलग करके एक नया मुक्तिमंडल जिला सन्कू बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन हुए, शायद इसलिए भी कि सदियों के दौरान यह इलाका अक्सर कारगिल से अलग रहता है। कारगिल से अलग करके एक नया जिला बनाने की इस किस्म की मांग झॉंस्कार के लोगों द्वारा भी की गई थी। यही बात लेह के सभी हिस्सों जैसे ड्रास, चांगथांग, खालस्ती और चुरुक के बारे में भी कही जा सकती है। हालांकि, क्या एक जिले का दर्जा देने की मांग के पीछे महज एक नई प्रशासनिक इकाई बनाने वाला औचित्य काफी है, जबकि इससे राजकाज पर काफी वित्तीय बोझ

पड़ता है। एक नया जिला बनते ही अतिरिक्त कर्मी, नए कार्यालय को बढ़ाया जाता है। नया जिला आम तौर पर उपखंड मुख्यालय को अपग्रेड कर बनाया जाता है, साथ ही पुलिस अधीक्षक और अन्य जिला-स्तरीय कार्यालय जैसे सहायक तंत्र की स्थापना करनी पड़ती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं क्योंकि संलग्न कार्यालय बनने में लंबा वक लगता है। कभी-कभी, बजटीय बाधाओं के कारण सभी विभागों को समकक्ष उच्च अधिकारियों वाले निजाम में क्या अब अधिक बेहतर देर से चल रहा है? और क्या यह सब पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक इस क्षेत्र के विकास की गुणवत्ता में सुधार लाया है।

मुख्य बिंदु यह है कि नया जिला बनने से जिलाधिकारी को अधिकारों का कोई बहुत बड़ा हस्तांतरण नहीं होता। इसलिए, यह समझना कठिन है कि यदि एक अधिकारी एक बड़े क्षेत्र को वर्तमान शक्तियों के साथ प्रभावी ढंग से प्रशासित नहीं कर पाया तो वह पूर्ववर्त शक्तियों के साथ छोटे क्षेत्र का कामकाज अधिक प्रभावकारी ढंग से कर पाएगा। यह शायद उस समय उचित था जब भौगोलिक दृष्टि से काम में देरी हुआ करती थी, लेकिन एक बृद्ध कार्यात्मक संचार नेटवर्क के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी-संचालित शासन तंत्र के युग में, निर्णय का अधिकार सौंपना अधिक संभव हो सकता है, जैसा कि दूर-दराज के बकीले जिलों में किया जाता है, जब वे दुर्गम बन जाते हैं, और निर्णय लेने वाली प्रैसी प्रणाली विकसित करना जो स्थायी स्तर पर एक अधिकारिता की मूलक संरचना के अतिरिक्त पर निर्भर न हो।

मुझे नहीं पता कि नई प्रशासनिक इकाईयों के निर्माण के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित करना संभव है या नहीं। उम्मेद यह कि पक्का नहीं है कि क्या हम व्यवहार्य जिले की अवधारणा विकसित कर सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में बनाए गए जिलों का लागत-ताम विरहलेपन करने की आवश्यकता है। एक नया जिला अधिक निष्पक्ष और शाहकरण को बढ़ावा देता है, लेकिन इससे क्या शासन और परिवारण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है? उदाहरण के लिए, यह एक विद्यालय मुद्रा है कि लदाख, जिसका प्रशासन पहले एक जिलाधीश द्वारा चलाया जाता था और वहां एक सशक्त स्वायत्त निर्वाचित परिषद थी, उसका कामकाज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक मुख्य सचिव, आबा दर्जन सचिवों और अन्य विभागों के समकक्ष उच्च अधिकारियों वाले निजाम में क्या अब अधिक बेहतर देर से चल रहा है? और क्या यह सब पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक इस क्षेत्र के विकास की गुणवत्ता में सुधार लाया है।

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार और तंत्र



-ललित गर्ग-

बांग्लादेश में हिन्दू मंदिरों पर हिन्दुओं को गंभीर हमले, नगराहू जंशेधरी मंदिर में युद्ध का प्रतीक, हिन्दू, अल्पसंख्यकों से जबरन हटाने के लिये दबाव बनाने की घटनाएं, दुर्गा पूजा के बहाल पर हमले विना के बड़े कारण हैं, यह हिन्दू और अल्पसंख्यकों को कुचलने की साक्ष्य है। अक्सर, जित पर भारत सरकार को गंभीर होने के साथ इन पर निवारण की ठोस कार्रवाहों की अपेक्षा है। बीते अक्सर में शुरू हुई राजनीतिक उद्वेग-पुनल के बीच श्रेय हनीना का प्रथममंत्री पर से हटाना और भारत आने के बाद बांग्लादेश में भारत धिकरे। गतिविधियों को असाधारण तौर व कहरपथियों द्वारा हवा दिया जाना शामिल एवं विडम्बनापूर्ण है। नई दिल्ली में बांग्लादेश के हिन्दू-अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रश्न को लेकर बार-बार विता ता चर्चा की जा रही है, लेकिन करण एवं सख्त संदेश देने की कोई कोशिश नहीं हुई नहीं दिख रही है। प्रथममंत्री नरेंद्र मोदी एवं मांजपा सरकार के शासन में यदि ऐसी घटनाओं पर सख्त नहीं बरती गयी तो फिर कम बरती जागी? यह विडम्बना है कि नरेंद्र मोदी पुरुरकार विजेता व कार्यालय रूप में सरकार के मुखिया का दायित्व निभा रहे मोक्षमय युसुस के कार्यकाल को हिन्दुओं एवं हिंदू पक्षान के प्रतीकों में विमाना बनाया जाना बहदतर रहना किसी अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य का हिस्सा हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख महंत परमानंद ने नागपुर में विजयदशमी पर्व पर आयोजित रेली को सम्बोधित करते हुए हिन्दुओं पर हो रहे इन हमलों को बंद कर देना संदेश दिया है, अपेक्षा है सरकार भी जैसे को तैसे जारी स्थिति में आकर हिन्दुओं की खास की साथक एवं प्रगामी बल करे।



महीने में बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदू मंदिरों पर हमले की 200 से अधिक घटनाएं हुईं। आज बांग्लादेश संसदीयिका को कहराशरी की आग में झुलस रहा है। धार्मिकता और धर्मिक कहरता लोकतंत्र के लिए बाधक बन रही है। दौराह पर बड़े बाधक हैं। खतरे की गभीरता को देखते हुए वह अंतरिम सरकार ने हिन्दू मंदिरों, पिरकाराओं या अल्पसंख्यकों के किसी भी धार्मिक स्थान पर हमलों की जांचकारी दंने के लिए हॉलंडलान शुरु की गयी, लेकिन बिकरुनी कहरपथियों ने यह खतरा बढ़ा जा रहा है। खतरे की गभीरता को देखते हुए वह अंतरिम सरकार ने हिन्दू मंदिरों, पिरकाराओं या अल्पसंख्यकों के किसी भी धार्मिक स्थान पर हमलों की जांचकारी दंने के लिए हॉलंडलान शुरु की गयी, लेकिन बिकरुनी कहरपथियों ने यह खतरा बढ़ा जा रहा है। खतरे की गभीरता को देखते हुए वह अंतरिम सरकार ने हिन्दू मंदिरों, पिरकाराओं या अल्पसंख्यकों के किसी भी धार्मिक स्थान पर हमलों की जांचकारी दंने के लिए हॉलंडलान शुरु की गयी, लेकिन बिकरुनी कहरपथियों ने यह खतरा बढ़ा जा रहा है।

कमी भारत की कोशिशों से ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। बांग्लादेश को अन्धी से ज्यदा विद्वली भारत से मिलती है। अनाज की बड़ी सप्लाई भी भारत से होती है। अगर भारत ने व्यापारिक संबंध तोड़ लिए तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था थोपट हो सकती है। बावजूद इन सब स्थितियों के वहां भारत-विरोधी घटनाओं का उभर उभर होना खुद के पांच पर कुल्हाड़ी चलाते जैसा है। बांग्लादेशी आकाओं को भगवान संकटबुद्ध है। फिर भी अगर बांग्लादेश नहीं सुखता है तो समय आ गया है कि हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाओं पर भारत कड़ा रुक अडिहार करे। बांग्लादेश पर दबाव बनाने के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को पुनरावेर ढंग से उठाना होगा। इसके लिए 'कुलीनिकी प्रयास तंत्र करने की जरूरत है।

हिन्दू धर्म भारत की संस्कृति एवं आत्मा है। हिन्दू धर्म संस्कृति, त्याग और बलिदान का धर्म है। इसमें हवाशा दुरेरे धर्म को समाप्त देने का काम किया है। हिन्दू धर्म पतन, भ्रम, आधारी सद्भाव और सनशीलता को साक्ष्यित धर्म है। हिन्दू धर्म की आधारभूतता को कमजोर करके हिन्दू धर्म की मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का कार्य लगातार होता रहा है। वैसे तो प्रत्येक धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं, किन्तु विकृत मानसिकता वाले लोगों के हिन्दू धर्म को मध्यकाल से ही गीबा दिखाने की कोशिशों की। भारत पर लगातार आकाओं के हमले होते रहे और बड़े पैमाने पर धर्महाराण कायम गया। हिन्दुओं के लाखों मंदिर तोड़े गए। हिन्दुओं से अपने ही धर्म में हिन्दू होने पर 'जजिया' यानि कर लगाया गया। पूर्ण की सरकारों ने भी वोट की राजनीति के लिये हिन्दुओं को दायम दर्जा के रखा। फिर भी हिन्दू धर्म ने उदारता और सहनशीलता को नहीं छोड़ा। अगर हिन्दू कहर मान मानवत में बड़े लोभ भी इन बातों का समर्थन करते हुए दिखे तो उसे सही नहीं कहा जा सकता। यह एक अपराजकता की स्थिति है।

काम का बढ़ता बोझ



-डॉ. शशांक द्विवेदी-

पिछले दिनों सत्तानज में एचडीडीसीबी बैंक में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी 45 वीं वयस तक फाल्गिनी की कथित रूप से वर्ष प्रेशर के चलते जान चली गई। इसके पहले घुमे में 'अनस्ट एंड यंग' में काम करने वाली एक युवा ली 26 साल की एना सेसेरिटीयन पेरालिजी की वर्ष प्रेशर के चलते मीत हो गई थी। इन दोनों की घटनाओं ने बिकिंग और वर्ष लाइफ बेल्ट्स को लेकर बहस छेड़ दी है।

एना और फाल्गिनी की मौत के बाद देश में वर्ष प्रेशर को लेकर बहस और चर्चाओं की तरफ रूख हो गई है। राजनीतिक दलों और बड़े डॉक्टरों ने भी सरकार को बताया है। डॉक्टरों की माने तो भारत में अवैतनिक का ड्रेड बंदक मोहन है। हाल के दिनों में ऑफिस और फैक्टरीयों के कर्मचारियों पर काम के दबाव के कारण मौत के कई मामले सामने आए हैं। रिसर्च में खुलासा हुआ है कि ज्यदातर युवाओं की मौत वर्ष प्रेशर की वजह से हुई है। इसे डॉक्टर औद्योगिकता डेस कहते हैं। ये मौत काम करते-करते हुईं। इनको फेक्टरीयों में काम करने वाला चाहिए। रिसेटोरे डेथ ट्रेडिंग जया चाहिए, इनको पुनर्जाया मिलना चाहिए। भारत विरहित देश की ओर अग्रसर है, ऐसे में कर्मियों और फैक्टरीयों में इस तरह की घटनाएं और बर्बादी। भारत सरकार को इसके लिए चुस्त ही कार्रवा जना चाहिए।

वैते तो भारत में बर्किंग और 8 से 9 घंटा का होता है। इस तरह लोग वयस 45 से 48 तक काम करते हैं। हालांकि, कुछ कर्मियों में बर्किंग और के बाद भी काम करना पड़ता है। इसकी वजह से न सिर्फ उनकी शारीरिक स्थिति पर असर पड़ता है, बल्कि काम के दबाव के चलते मानसिक तौर पर कुमिया की कमजोरी हो जाती है। हालांकि, कर्मियों के कुछ पैसा मिल रहे हैं, जहां वह कई लाइफ बेल्ट्स काफी ज्यदा देना है। यहां लोग बहते में 30 घंटे या उससे भी काम कर सकते हैं।

इसे रजिस्ट्रार के अंतर्गत नेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रॉब्लम महासगर में स्थित नाना काम के देस में सबसे काम घटे तक लोग काम करते हैं। 7 घंटे काम करती हैं। वयस 45 फीसदी की घटाव की स्थिति 2.7 घंटे काम करता है। इसकी की 4 फीसदी आवादी की स्थिति में 49 घंटे या उससे ज्यदा काम करती हैं। इसका अर्थ है कि भारत वयस कम उमरकी पंजी ने कंपनी से मुनाजाना मिलेगी। कंपनी ने मुनाजाना नहीं दिया तो इनको लेकर एसीआरएन बना। 6 उमरकी पंजी और लोग भी सामने आए, इसके बाद यह मांग परिष्कृत की गई तब हिन्दू शक्तिस्मन हवाकों की निवृत्त बन रहे लगी। इन हवाकों के जवब तत्समने होंगे वना हिन्दुओं को अतिरिक्तीयन करने की कोशिशें कामयाब होती रहेंगी।

-लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

